भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1508
दिनांक 7 दिसम्बर, 2021 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम

1508. श्री पी.पी. चौधरीः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) के अभिसरण के माध्यम से डेयरी उद्यमियों/डेयरी उद्योग को लाभ देने का कोई विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत कितनी निधि जारी की गई है; और
(घ) इस योजना के तहत राजस्थान में प्राप्त और स्वीकृत परियोजनाओं और प्रस्तावों की संख्या कितनी है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) और (ख) हाल ही में, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) योजना को जुलाई 2021 में पुनर्गठित/पुनर्संगठित किया गया है। पुनर्गठित एनपीडीडी योजना वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 तक क्रियान्वित की जायेगी और इसमें दो घटक होंगे ;

घटक 'क' प्राथमिक प्रशीतन सुविधाओं के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण दुग्ध परीक्षण उपकरण हेतु अवसंरचना सृजन/सुदृढ़ीकरण की ओर ध्यान केंद्रित करता है।

घटक 'ख' (सहकारिता के माध्यम से डेयरी-डीटीसी) आवश्यक डेयरी अवसंरचना के सृजन, गांव की उपज हेतु बाजार पहुंच उपलब्ध कराने और गांव से लेकर राज्य स्तर तक की हितधारी संस्थाओं की क्षमता निर्माण के सुदृढ़ीकरण हेतु जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

एनपीडीडी (घटक 'क') के माध्यम से वित्तीय सहायता का लाभ लेते हुए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों द्वारा डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु प्रावधान किए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम योजना के तहत वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के दौरान क्रमश: 266.17 करोड़ रू और 285.86 करोड़ रू की राशि जारी की जा चुकी है।

(घ) एनपीडीडी योजना के तहत राजस्थान से प्राप्त कुल 20 परियोजना प्रस्ताओं में से, 19 परियोजनाओं को कुल 179.25 करोड़ रू (केंद्र का हिस्सा 144.45 करोड़ रू) के अनुमोदित परिव्यय के साथ संस्वीकृति दी गयी है।

****